IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 10, April 2025
Impact Factor: 7.67

प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न उपागम के सन्दर्भ में नई शिक्षा नीति के प्राथमिक स्तर के पहल पर प्रकाश

सुप्रिया श्रीवास्तव and *डॉ.राघवेंद्र मालवीय **

*शोधार्थीनी,शिक्षक शिक्षा विभाग,

** असिस्टेंट प्रोफेसर(शिक्षक शिक्षा विभाग)

नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), जमुनीपुर कोटवा, प्रयागराज,उ.प्र.

संक्षिप्त सार

प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षा पद्धति का उद्देश्य भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करना रहा है। समाज का बौद्धिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष शिक्षा के माध्यम से माना गया है। ऋग्वेद में विद्या को मानव की श्रेष्ठता का आधार माना गया है। शिक्षा मानव जीवन का आधार है। शिक्षा मानव के जीवन की प्रगति पथ पर पहली सीढ़ी है। शिक्षा के मायने विभिन्न हैं, यह केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है वरन् यह बहुआयामी है। इसके बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, व्यापारिक आदि विभिन्न आयाम है। ये सभी आयाम हमें अपने जिंदगी के किसी न किसी मोड़ में सहयोग प्रदान करते हैं। शिक्षा न केवल हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है वरन् ये हमें जिंदगी में सही फैसले लेना और जिंदगी से सामंजस्य बैठाना भी सिखाती है।आदिकाल से ही भारतीयों में शिक्षा के प्रति आदर भाव रहा है, जब शेष दुनिया खाना-बदोश थी तब भारत में वेदों की रचना हुई। सिंधु सभ्यता के प्रमाण भी बताते हैं कि भारत में तकनीक, भवन निर्माण आदि कलाओं में कितने पारंगत थे। भारत कई शताब्दियों तक विदेशी आक्रांताओं के अधीन रहा। देश के सभी वर्ग के लोगों के अथक प्रयास से भारत को आजादी मिली। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् दुनिया के सभी संविधानों से प्रेरणा लेकर विश्व के सबसे बड़े संविधान का निर्माण किया गया लेकिन भारतीय शिक्षा मैकाले की शिक्षा से आजाद नहीं हो सकी। भारत में आजादी के पश्चात कोठारी आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशें के आधार पर 1968 में भारत की प्रथम शिक्षा नीति आई, 1986 में सरकार ने नयी शिक्षा नीति बनायी जिसमें 1991 में कुछ संशोधन किए गए और 2009 में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लाया गया। इन सभी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य लोगों तक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना था ताकि सभी शिक्षा से जुड़ सके और शिक्षा समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ हो सके। 21वीं सदी का भारत इन सबसे बढ़कर कुछ अलग और ऐसी शिक्षा नीति की उम्मीद करता है जो उसे वर्तमान परिस्थितियों से सामना करने में सक्षम बना सके। वास्तव में शिक्षा समावेशी हो, रोजगारपरक हो, भारतीय चिन्तन एवं दर्शन एवं भारत केन्द्रित शोध पर आधारित हो ताकि शिक्षा सभी के विकास में महत्तवपूर्ण योगदान दे सके तथा ऐसी न हो जिससे वे पढ़े-लिखे डिग्रीधारी बेरोजगार हो सकें। उक्त के आलोक में वर्तमान सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लायी गयी है। यह शिक्षा नीति छात्रों के विशिष्ट क्षमताओं की पहचान और विकास, शिक्षा के ढांचे को लचीला, सीखने पर जोर, छात्रों में जोर देना व तार्किक और रचनात्मक सोच का विकास, रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 10, April 2025
Impact Factor: 7.67

देने के लिए है। इस नीति के अनुसार विद्यालयीन शिक्षा को 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 कर दिया गया है। 5(आँगनवाड़ी + प्री स्कूल + कक्षा 1 और 2), 3(कक्षा 3 से 5), 3(कक्षा 6 से 8) और 4 (कक्षा 9 से 12) शामिल है। इस शोध कार्य के लिए द्वितीय स्तर के सूचनाओं को शामिल किया गया है।

मुख्यशब्द :-*प्राथमिक शिक्षा,उपागम,शिक्षा निति पहल* आदि।